(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक से सहायता कुल राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	विश्व बैंक से प्राप्त सहायता (रुपए लाख में)
1995-96	949.41
1996-97	1447.88
1997-98	-*

*परियोजना के तहत ऋण राशि के निलम्बन के कारण इस अवधि के दौरान कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई थी।

देश में खाद्यान्न उत्पादन

3218. **श्री ओंकार सिंह लखावत:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हमारे देश में गत वर्ष गेहूं, चावल, ज्वार-बाजरा इत्यादि जैसे खाद्यान्नों का कुल कितना उत्पादन हुआ और इन खाद्यान्नों की वार्षिक मांग कितनी है;

(ख) अनाज, दालों, तिलहन व अन्य खाद्यान्नों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की योजना क्या है; और

(ग) खाद्यान्न उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) पिछले वर्ष अर्थात् 1996-97 के दौरान गेहूं, चावल, मोटे अनाजों, दलहनों और सभी खाद्यान्नों का अखिल भारतीय उत्पादन क्रमशः 69.27, 81.31, 34.28,14.46 और 199.32 मिलियन मी० टन था।

निर्धारित समय में चावल, गेहूं आदि जैसी विशेष जिन्सों की वार्षिक मांग जनसंख्या की विशेषताओं, उत्पादन, उपलब्धता, आय वितरण, मूल्य प्रवृत्ति, उपभोक्ता प्रवृत्ति, विकल्प की उपलब्धता और अन्य संबंधित मामलों जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। इस प्रकार पूर्णतया सही वार्षिक मांग का निर्धारण करना कठिन है। नौवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के लिए कृषि जिन्सों की मांग और आपूर्ति प्रक्षेपण तथा कृषि सांख्यिकी के विकास संबंधी कार्यकारी दल ने 1996-97 के लिए 185.50 मिलियन मी० टन खाद्यान्नों की मांग का अनुमान लगाया है।

(ख) खाद्यान्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए सरकार गेहूं, चावल और मोटे अनाजों पर आधारित फसल प्रणाली क्षेत्रों में केन्द्रीय प्रायोजित समन्वित अनाज विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना कार्यान्वित कर रही है। इन कार्यक्रमों को नौवीं योजना में जारी रखने का प्रस्ताव है।

(ग) 1996-97 के दौरान राजस्थान में खाद्यान्नों का उत्पादन 12.84 मिलियन मी०टन था जो देश में उत्पादित कुल खाद्यान्नों का 6.44 प्रतिशत है।

Infrastructural Facilities for Seed Production

3219. SHRI W. ANGOU SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the steps taken by Government to strengthen infrastructural facilities for seed production in the country; and

(b) what are the special facilities for strengthening seed production in the North-Eastern State?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI SOMPAL): (a) With the objective of strengthening infrastructural facilities for seed production, the National Seeds Corporation (NSC), the State Farms Corporation of India Ltd. (SFCI) and 13 State Seeds Corporations have been established in the country. In addition an infrastructure for certification of seeds under the provisions of the Seeds Act has been established. In the VIIIth Five Year Plan the Government of India has implemented a number of Central Sector/ Centrally Sponsored Schemes for strengthening facilities in the seed sector. Assistance has been provided to organisations engaged in production and quality certification of seeds under the National Seed Project-III, National Programme for Varietal Development, Integrated Seed Development Programme for not easily accessible and remote areas and scheme for Quality Control Arrangement on seed. Under these scheme assistance was provided to